

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बर्डजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 6/2020/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांक: 6.1.2020

अन्तर्गत धारा: 18 आर्म्स एक्ट, 1959

उनवान

रूपसिंह आत्मज कान्हसिंह जाति राजपूत निवासी भाटों का खेडा थाना गेण्डोली जिला बूंदी-राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर बूंदी।
2. जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी
3. जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी
4. थानाधिकारी थाना गेण्डोली जिला बूंदी।



... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री तंवर सिंह पितलावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोंड


:::निर्णय:::

दिनांक 3.2.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/2019/11479 दिनांक 4.11.2019 (संक्षेप मे अपीलार्थीनिर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 6.1.2009 को आवेदन पत्र अधीनस्थ कार्यालय मे पेश किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र को पूर्व आदेश क्रमांक 1107 दिनांक 14.2.2012 से निरस्त कर प्रार्थी को जेरअपील आदेश/पत्र से सूचित किये जाने पर अपील सं0 40/12 न्यायालय हाज मे पेश की गई जिसको निर्णय दिनांक 5.11.2012 से रिमांड किया गया। रिमांड आदेश की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अनुशंषा नहीं किये जाने पर पुनः दिनांक 28.4.2016 को आवेदन पत्र निरस्त किया गया जिसकी अप्रसन्नता से पुनः अपील सं0 63/16 न्यायालय हाजा मे पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 6.2.2017 से पुनः प्रकरण रिमाण्ड किया गया। न्यायालय हाजा के रिमांड आदेश की पालना मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीन लाईसेन्स जारी किये जाने की अनुशंषा नहीं किये जाने पर दिनांक 19.6.2017 को पुनः आवेदन पत्र निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा पुनः न्यायालय हाजा मे अपील सं0 30/18 पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 8.4.2019 अनुसार प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। न्यायालय हाजा के रिमांड आदेश की पालना मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को नवीनशस्त्र जारी करने की अनुशंषा नहीं की गई अतः अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 6.1.2009 को प्रस्तुत आवेदन पत्र को पुनः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी द्वारा आदेश क्रमांक 11479 दिनांक 4.11.2019 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया गया कि बूंदी द्वारा आदेश क्रमांक 11479 दिनांक 4.11.2019 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून एवं तथ्यों के विरुद्ध है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड आदेश की पालना मे पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण न कर दुबारा नया शस्त्र चाहने बावत प्रक्रिया पुनः शुरू की जो रिमांड आदेश के विपरीत है। पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 30.6.2009 अपीलार्थी के पक्ष मे जारी की गई इसी प्रकार थानाधिकारी गेण्डोली का चरित्र प्रमाण दिनांक 17.4.2012 व तहसीलदार बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 20.7.2009, सीआईडी सीबी (इन्टे0) जोन कोटा की रिपोर्ट दिनांक 24.11.2010

- मण्डल वन अधिकारी बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.7.2011 पुलिस अधीक्षक की पुनः ली गई रिपोर्ट दिनांक 5.10.2011 , शस्त्र प्रशिक्षण के संबंध में जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19.6.2011 जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 30.5.2013 अपीलांत के पक्ष में जारी की गई थी। उक्त सभी तथ्यों के होते हुये भी थानाधिकारी गेण्डोली की अपीलांत के पक्ष में जारी एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर वृत्ताधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अपीलांत के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने की अनुशंसा के आधार पर ही अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील आदेश दिनांक 4.11.2019 पारित कर दिया जो अपीलांत के हितों के विरुद्ध है। अपीलांत के पास स्वयं की कृषि भूमि है नया शस्त्र 12 बोर बन्दूक का लाईसेन्स आत्म रक्षा हेतु चाहा गया है जिसके लिये अपीलार्थी पात्र होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेरअपील पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी का आदेश दिनांक 4.11.2019 अपास्त कर अपीलांत के पक्ष में नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आदेश प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की गई।
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।
 - 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड आदेश की पालना में पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण न कर दुबारा नया शस्त्र चाहने बावत प्रक्रिया पुनः शुरू की जो रिमांड आदेश के विपरीत है। पत्रावली में सभी वांछित रिपोर्ट अपीलांत के पक्ष में थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया तथा पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार बनाकर जेरअपील आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलांत को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर जेरअपील आदेश से आवेदन पत्र निरस्त कर विधिक त्रुटि की है। अंत में अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त कर अपीलांत के पक्ष में नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।
 - 4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांत को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अनुशंसा नहीं किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर सूचित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश न्यायोचित होने से अपील खारिज की जावे।
 - 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख व आलोच्य जेरअपील आदेश दिनांक 4.11.2019 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 6.1.2009 को प्रस्तुत आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की अनुशंसा नहीं की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में अपीलांत के आवेदन पत्र को 3 बार निरस्त किया है जिसकी अपील न्यायालय हाजा में पेश करने पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जाता रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्व में अपीलांत के प्रकरण को 3 बार क्रमशः दिनांक 5.11.2012, 6.2.2017 व 8.4.2019 को अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जा चुका है। रिमांड आदेश की पालना में सक्षम अनुज्ञापति अधिकारी का लगातार यह मत रहा है कि अपीलार्थी को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आलोच्य आदेश दिनांक 4.11.2019 से अपीलार्थी के नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया है। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख उपखण्ड मजि0 बूंदी की रिपोर्ट क्रमांक 995 दिनांक 10.3.2014 एवं जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक 9.11.2017 के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में कोटा में निवास करता है। अपीलार्थी को जीवन से खतरे का कोई विशिष्ट तथ्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2019/11479 दिनांक 4.11.2019 को न्यायोचित पाते हैं। उक्त विवेचन अनुसार परिणाम स्वरूप अपील अपीलांत सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।
 - 6 निर्णय आज दिनांक 3.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।


 (एल. एन. सोनी)
 संभागीय आयुक्त
 कोटा, कोटा